IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कीमतें और मुद्रास्फीतिः उतार – चढाव को समझना

वरुण प्रसाद सेमवाल

असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र

सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी0जी0) कॉलेज साहिया,

देहरादून, (उतराखण्ड)

सारांशः वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति में मुद्रास्फीति का महत्वपूर्ण स्थान है। 2022 में आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और भू–राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक मुदरास्फीति उच्चतम स्तर पर थी, लेकिन नीतिगत उपायों से इसमें गिरावट आई है। भारत में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के समयबद्ध हस्तक्षेपों के कारण 2025 के वित्तीय वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आई, कोर मुद्रास्फीति एक दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंची, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं और प्रतिकूल मौसम से प्रभावित रही। प्याज और टमाटर की कीमतों पर उत्पादन में गिरावट और मौसम की चरम स्थितियों के कारण असर पडा है। दलहन के मामले में भारत को मांग और आपूर्ति में अंतर का सामना करना पड रहा है, हांलाकि सरकार ने प्याज, टमाटर और तिलहन के लिए मूल्य स्थिरीकरण उपाय किए हैं, जैसे कि भंडारण, रियायती दरों पर बिक्री और आयात को सरल बनाना। अनुमान है कि भारत की मुद्रा स्थिति धीरे–धीरे लक्ष्य के अनुरूप होगी और वैश्विक पण्य (कमोडीटी) की कीमतों में गिरावट से कोर और खाद्य मुद्रास्फीति में और कमी आ सकती है। दीर्घकालिक कीमत स्थिरता के लिए जलवायु–प्रतिरोधी फसलों का विकास और मजबूती डेटा प्रणालियां आवश्यक होगी।

शब्द कुंजीः वैश्विक अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, नीतिगत उपाय, भारतीय रिजर्व बैंक, खुदरा मुद्रास्फीति, कोर मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति और मूल्य स्थिरीकरण।

प्रस्तावनाः वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की गतिशीलता को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नीति निर्माताओं और आम जनता के लिए कई आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न करती है। वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक सुधार के बीच संतुलन बनाने के लिए सावधानी पूर्वक अपनी नीतियों में ढील दे रहे हैं। भारत में भी विभिन्न सरकारी पहल और मौद्रिक नीति समीक्षाएं मुद्रास्फीति दबाव को नियंत्रण में रखने में सहायक रही हैं। वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और भू–राजनीतिक तनावों के कारण 8.7 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, लेकिन 2024 में 5.4 प्रतिशत से घटकर वित वर्ष 2025 (अप्रैल–दिसम्बर) में 4.9 प्रतिशत हो गई है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो खुदरा मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है। खाद्य मुद्रास्फीति, हेडलाइन मुद्रास्फीति, में एक प्रमुख हिस्सेदरी रही है हालांकि यह सभी खाद्य श्रेणियों में समान रूप से नहीं पढ़ी है। इस शोध पत्र में कुछ प्रमुख खाद्य वस्तुओं का केंद्रीय विश्लेषण किया गया है, जैसे प्याज और टमाटर खाद्य मुद्रास्फीति पर ऊपर की और दबाव डालती है। इस शोध

पत्र को खंडों में विभाजित किया गया है। पहले वैश्विक मुद्रास्फीति का विश्लेषण किया गया है, और फिर घरेलू मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों की जांच की गई, और मुद्रास्फीति की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले निकटतम कारकों पर चर्चा की गई है। इसके बाद मुद्रास्फीति प्रबंधन के कुछ सिफारिशें दी गई है।

साहित्य समीक्षा

मिल्टन फ्रीडमैन ने मुद्रास्फीति को एक मौद्रिक परिघटना बताते हुए यह विचार रखा कि दीर्घ में वृद्धि ही मुद्रास्फीति का कारण बनती है। उनके अनुसार, यदि केंद्रीय बैंक अनियंत्रित रूप से मुद्रा छापे, तो मुदास्फीति अपरिहार्य हो जाती है।

जॉन मेनार्ड कीन्स का मत इससे थोडा भिन्न था। उन्होंने माना कि अल्पकाल में मांग और खर्च की प्रवृत्ति भी कीमतों को प्रभावित करती है। उनकी दृष्टि में सरकारी खर्च, उपभोग और निवेश की प्रवृत्तियां कीमतों में उतार–चढाव का कारण बनती हैं।

भारतीय सन्दर्भ में, डॉ. मनमोहन सिंह ने 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान बार–बार इस बात पर जोर दिया कि मूल्य स्थिरता के बिना आर्थिक विकास असंभव है। उनके अनुसार, एक संतुलन मौद्रिक नीति और राजकोषीय अनुशासन मुद्रास्फीति नियंत्रण के मुख्य साधन हैं।

शोध के उद्देश्य– 1. वैश्विक और घरेलू मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना और उन कारकों की पहचान करना।
2. उन वस्तुओं का विश्लेषण करना है, जो मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है।

शोध प्रविधि–यह शोध पत्र मूलतः द्वितीयक समंको पर आधारित है। द्वितीयक समंकों का संकलन, आर्थिक सर्वेक्षण, आई.एम.एफ, आई.एम.डी, विश्व बैंक एवं अन्य पत्रिकाओं से किया गया है। समंकों के विश्लेषण में प्रतिशत विधि एवं आवश्यकतानुसार अन्य विधियों का प्रयोग किया गया है।

वैश्विक मुद्रास्फीति

समकालिक मौद्रिक नीति सख्ती के बीच वैश्विक लचीलापन– वैश्विक अर्थव्यवस्था ने मौद्रिक नीति में तीव्र एवं समकालिन सख्ती के बावजूद उत्पादन वृद्धि में लचीलेपन का प्रर्दशन किया है। वित्त वर्ष 2024 और चालू वर्ष में अधिकांश देशों में हैडलाइन मुद्रास्फीति दर में गिरावट देखी गई है। केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों और अन्य नीतिगत उपायों के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के ठोस प्रयासो से मुद्रास्फीति दबावों में उल्लेखनीय कमी आई है।

विभिन्न देशों में हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी मौद्रिक लक्ष्यीकरण में वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति को कम किया और उत्पादन को स्थिर किया

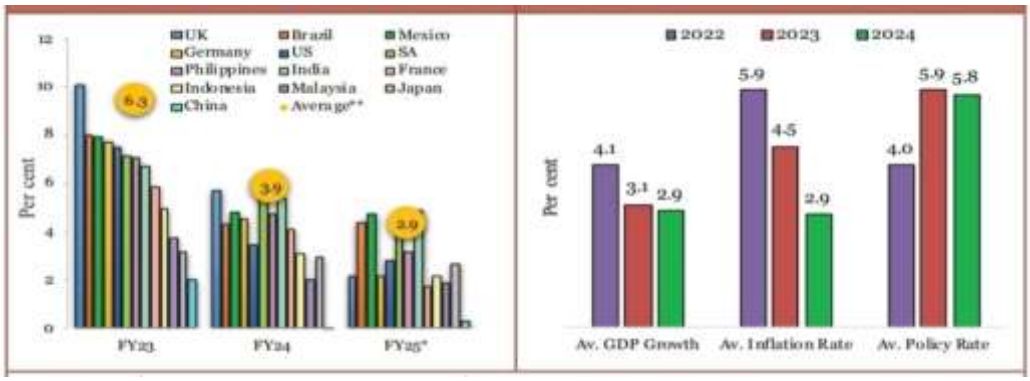

स्रोतः ब्लूमबर्ग और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आईएमएफ डब्ल्यूईओ डेटाबेस अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025 तक अद्यतन, केंद्रीय बैंक नीति दरें, बीआईएस

कोर मुद्रास्फीति में गिरावट– हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ–साथ, कोर मुद्रास्फीति भी अधिकांश देशों देशों में कम हुई है, जिसमें अस्थिर खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं है। इस गिरावट का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय पण्य (कमोडीटी) कीमतों में नर्मी है। यह प्रवृत्ति नीतिगत हास्तक्षेपों की प्रभावशीलता को दर्शाती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में कीमतों को स्थिर करने में सहायक रहते है।

कोर मुद्रास्फीति भी कम हुई है

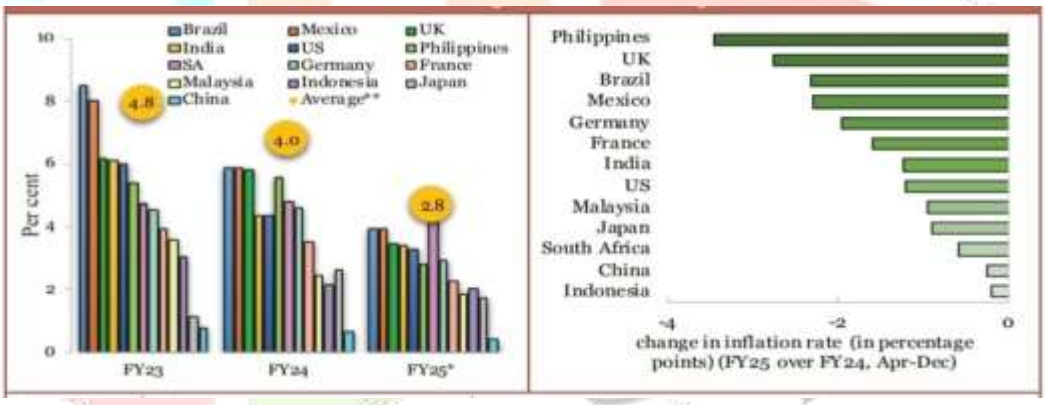

स्रोतः ब्लूमबर्ग और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई है लेकिन कुछ उभरती अर्थव्यवस्था में भिन्नता बनी हुई है– वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट आ रही है, जो हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति में देखी गई गिरावट के अनुरूप है। अच्छी फसल और अनुकूल परिस्थितियों के कारण वैश्विक आपूर्ति स्थितियों में सुधार हुआ, जिससे खाद्य किमतों में नरमी आई है, हालांकि, ब्राजील, भारत और चीन जैसी कुछ उभरती अर्थव्यवस्था में विपरीत पैटर्न देखा जा रहा है।

वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट कुछ उभरती अर्थव्यवथाओं में अलग–अलग प्रवृति

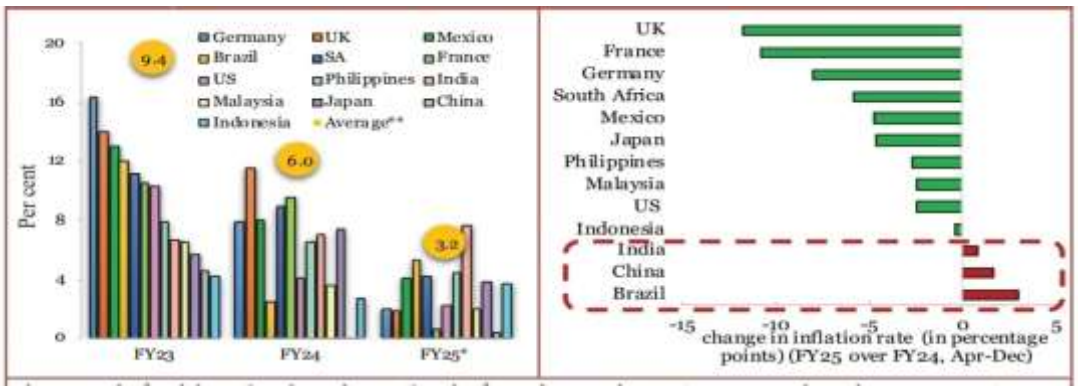

स्रोतः ब्लूमबर्ग और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

घरेलू मुद्रास्फीति

कोर मुद्रास्फीति में नरमी से हैडलाइन में कमी –भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल –दिसंबर) में वित्त वर्ष 2024 के तुलना में कम हुई है, जो मुख्य रूप से कोर मुद्रास्फीति में 0.9 प्रतिशत बिंदु की कमी के कारण है, कोर सेवा मुद्रास्फीति में गिरावट ने इसे बढ़ाया, जबकि कोर वस्तु मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत स्थिर रही। ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति में कमी ने भी मुद्रा स्थिति में गिरावट में योगदान दिया। थोक मुल्य मुद्रास्फीति ने भी इस गिरावट को परिलक्षित किया, जो वित्त वर्ष 2024 में अपस्फीति जोन (–0.7 प्रतिशत) में थी और 2025 में काम रही।

हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति नियंत्रण में

स्रोतः केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

खाद्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से कुछ खाद्य वस्तुओं के कारण–भारत की खाद्य मुद्रास्फीति दर पिछले दो वर्षों में स्थिर रही है, जबकि वैश्विक रूझान में खाद्य मुद्रास्फिीति घट रही है। इस कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान मौसम की आसमान्य स्थितियां और कुछ खाद्य पदार्थों की कम पैदावार के कारण हो सकता है। सीएफपीआई द्वारा आंकी गई खाद्य मुद्रास्फिीति में वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल–दिसंबर) में खाद्य मुद्रास्फीती में वृद्धि देखी गई, खासकर सब्जियों और दलहन के कारण, जिनका सीपीआई बास्केट में कुल वजन 8.42 प्रतिशत है। इन वस्तुओं के योगदान से खाद्य मुद्रास्फीति में 32.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । जब सब्जियों और दलहन को बाहर रखा गया तो खाद्य मुद्रास्फीति 4.3 प्रतिशत हो रही, जो समग्र खाद्य मुद्रास्फीति से 4.1 प्रतिशत कम है। बिना सब्जियों और दलहन के हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.2 प्रतिशत होती, जो वास्तविक हेडलाइन मुद्रास्फिीति से 1.7 प्रतिशत कम है, मानसून में असमानाता और आपूर्ति में व्यवधान (जैसे– टमाटर और प्याज की किमतों में वृद्धि) से सब्जियों की मुद्रास्फीति दर बढ़ी। सीपीआई बास्केट से टमाटर प्याज और आलू (टी–ओपी) को बाहर करने पर

औसत खाद्य मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत और हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत रही है, जो वर्तमान हैडलाइन मुद्रास्फीति से 0.7 प्रतिशत कम है।

सब्जियों और दलहन के कारण खाद्य मुद्रास्फीति

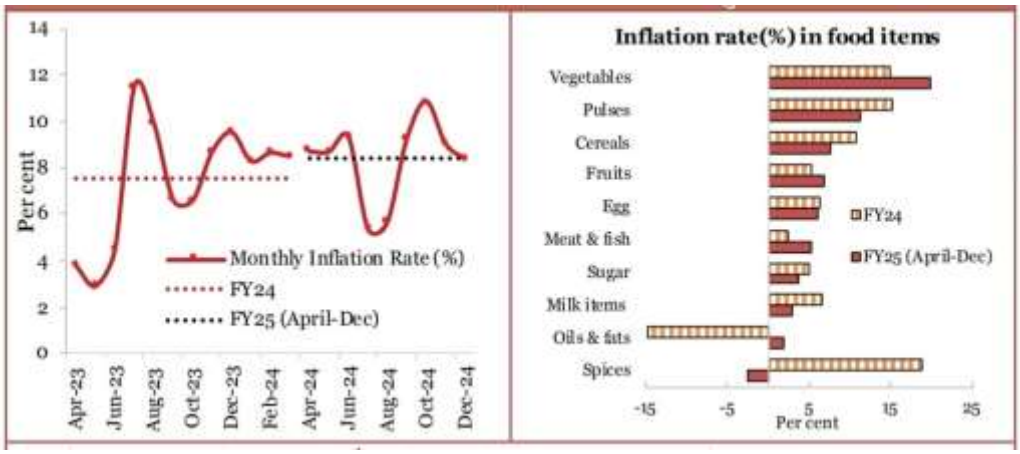

स्रोतः केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

टमाटर की खुदरा कीमतों में वृद्धि 2024 में उच्च अस्थिरता का संकेत देती है

2024 में प्याज की खुदरा कीमतें ऊंची बनी रही

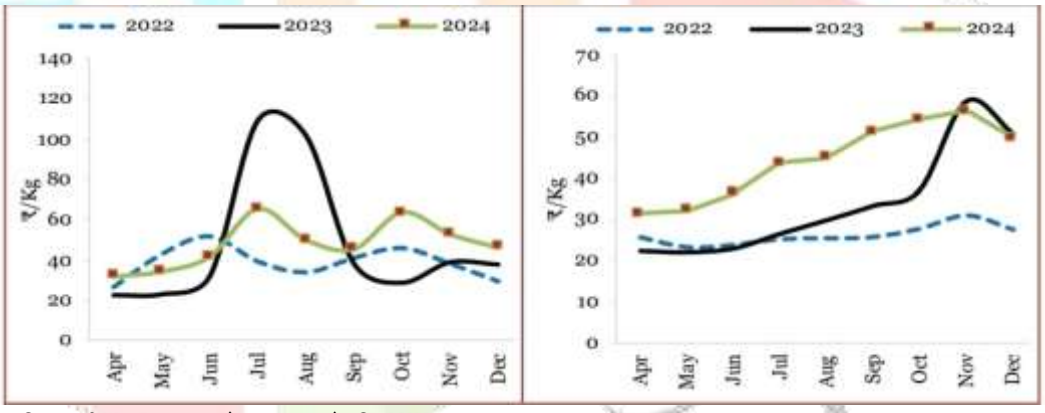

स्रोतः मूल्य निगरानी प्रभाग, उपभोक्ता मामले विभाग

चरम मौसम स्थितियां सब्जी उत्पादन और कीमतों को प्रभावित करती हैं।

विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि असमान मौसम का प्रभाव का प्रभाव खाद्यानों के मुकाबले सब्जियों पर अधिक पड़ता है। चरम मौसम की घटनाएं, जैसे चक्रवात भारी वर्षा, आंधी, ओलावृष्टि और सूखा सब्जियों की कीमतों को प्रभावित करती है। 2023–24 में बागवानी वस्तुओं की मुद्रास्फीति का करण बेमौसम बारिश थी, जिसने प्रमुख बागवानी उत्पादक राज्यों में फसलों को नुकसान पहुचाया। मौसम की घटनाएं उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करती हैं, जिससे खुद्रा कीमतें अस्थिर होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022–2024 के बीच हांटवेव की आवृत्ति बढ़ी है, जहां 2020–21 में 5 प्रतिशत दिनों की तुलना में 18 प्रतिशत दिनों में हांटवेट का अनुभव हुआ। सीएसई और डीटीई के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में चरम मौसम के कारण फसल क्षेत्र में अधिक नुकसान हुआ।

प्याज और टमाटर के उत्पादन और कीमतों की प्रवृत्ति–कम उत्पादन और सीमित आपुर्ति के करण सरकार द्वारा त्वरित उपयों के बावजूद, 2024 और 2025 में प्याज और टमाटर में मुद्रास्फीति का दबाव बना रहा। प्याज रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है, और 70 प्रतिशत उत्पादन रबी मौसम के दोरान होता है। रबी

मौसम में काटे गए प्याज का भंडारण लंबे समय तक होता है, जिससे मूल्य में उतार–चढ़ाव होता है। 2022–23 और 2023–24 में कम उत्पादन के कारण प्याज में मुद्रास्फीति बढ़ी है। वहीं टमाटर का फसल चक्र छोटा और जल्दी खराब होने वाला होता है, जिससे भंडारण और परिवहन में कठिनाइयां आती है और आपुर्ति में कमी होती है। टमाटर का मुख्य रूप से कुछ राज्यों में संकेंद्रीत है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में क्षेत्रीय व्यवधान हो सकता है। टमाटर का अधिकांश उत्पादन 65 प्रतिशत रबी मौसम में होती है, जिससे कीमतों में उतार–चढ़ाव जारी रहता है।

विभिन्न क्षेत्रों में प्याज उत्पादन की प्रवृत्ति

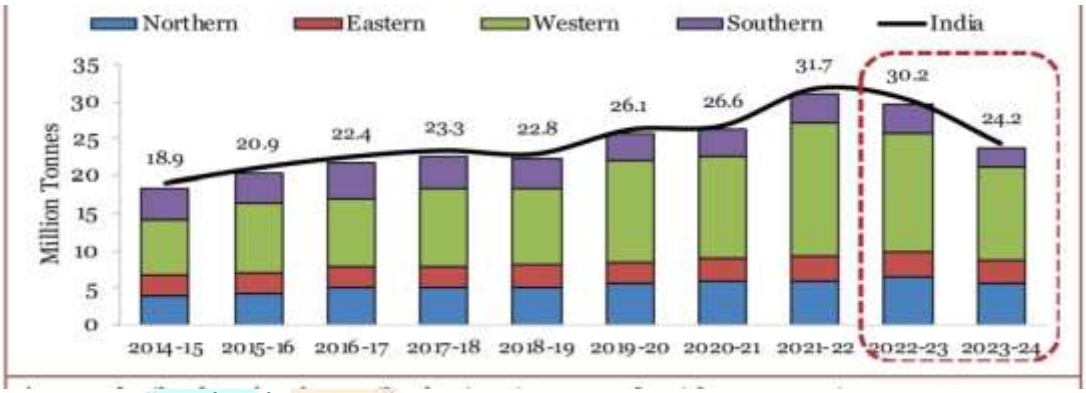

स्रोतः बागवानी सांख्यिकी इकाई, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

प्याज और टमाटर का फसल–कैलेंडर

सब्जी	उत्पादन में हिस्सा	मौसम	प्रत्यारोपण	कटाई अवधि
प्याज	30%	खरीफ	जुलाई - अगस्त	अक्टूबर-दिसंबर
		खरीफ	अक्टूबर-नवंबर	जनवरी - मार्च
	70%	रबी	दिसंबर - जनवरी	मार्च के अंत से मई तक
टमाटर	33%	खरीफ	मई-जुलाई	जुलाई-सितंबर
	67%	रबी	अक्टूबर-नवंबर जनवरी-फरवरी	दिसंबर-जून

स्रोतः प्रेस सूचना ब्यूरो विज्ञप्ति, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

टमाटर और प्याज के अतिरिक्त, अरहर दाल ने भी भारत में खाद्य मुद्रास्फीति में योगदान दिया। अरहर दाल के उत्पादन में 2022–23 और 2023–24 में गिरावट आई, जिससे 2024 और 2025 (अप्रैल–दिसंबर) में कीमतों में वृद्वि हुई। 2022–23 में उत्पादन में 13.6 प्रतिशत और 2023–24 में 10.8 प्रतिशत की कमी आई, जिससे आपूर्ति प्रभावित हुई। सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में अरहर की मांग को पूरा करने के लिए 7.5 लाख टन अरहर का आयात मोजांबिक, तंजानिया, मलावी और म्यांमार से किया गया।

निष्कर्ष–

भारतीय रिजर्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया है कि भारत की उपभोगता मुल्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2026 में लक्ष्य की ओर बढ़ेगी, जिसमें 2025 में 4.8 प्रतिशत और 2026 में 4.2 प्रतिशत मुद्रास्फीति का अनुमान है। विश्व बैंक के कमोडिटी मार्कोट्स आउटलुक, अक्टूबर 2024 के अनुसार, 2025 में 5.1 प्रतिशत और 2026 में 1. 7 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है, जबकि तेल और गैस की कीमतों में भिन्नताएं होगी। भारत के आयातित वस्तुओं की किमतों में गिरावट घरेलू मुद्रास्फीति के लिए सकारात्मक है।

2024 में सामान्य मानसून और जलाशयों के जल स्तर में सुधार से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति तेल की किमतों में वृद्धि खाद्य मुद्रास्फीति के लिए जोखिम हो सकती है। सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉफ बाजार में आपूर्ति और स्टॉक सीमा जैसी उपायों को लागू किया है। भविष्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने जलवायु और परिवर्तन के प्रति सहनशील फसल किस्मों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इसके साथ मूल्य निगरानी और डेटा संग्रह प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके और नीतिगत निर्णय सही समय पर लिए जा सके।

संदर्भ–

1. ब्लूमबर्ग और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आईएमएफ डब्ल्यूईओ डेटाबेस अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025 तक अद्यतन, केंद्रीय बैंक नीति दरें, बीआईएस
2. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
3. मूल्य निगरानी प्रभाग, उपभोक्ता मामले विभाग
4. बागवानी सांख्यिकी इकाई, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
5. प्रेस सूचना ब्यूरो विज्ञप्ति, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
6. विश्व बैंक कमोडिटी मार्केट आउटलुक, अक्टूबर 2024 (https://tinyurl.com/dyduh9tu)
7. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
8. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2025, जनवरी) वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेटः ग्लोबल ग्रोथः डाइक्जेंट एंड अनसर्टन वाशिंगटन, डीसी। (https://tinyurl.com/29uss/2x)
9. राया, डी. और रॉय, आर (2023). बागवानी फसलों में बेमौसम बारिश और मूल्य वृद्धि। क्लाइमेट रूफिंग एग्रीकल्चर एग्री–फूड ट्रेंड्स एंड एनालिटिक्स बुलेटिन वोल 3. इश्यू1. (https://tinyurl.com/yyr8fzek)
10. आर्थिक समीक्षा (2024–2025)